कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री एस0आर0 बालासुब्रहमण्यन**) : (क) से (घ) बहुत सी राज्य सरकारों, यथा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा तथा राजस्थान की राज्य सरकारों ने यह रिपोर्ट किया हैं कि वे जनता को एक या अधिक क्षेत्रों से संबंधित सरकार की कार्रवाई और रैका ई संबंधी सूचना तक आबाध और आसान पहुंच मुहैया करवा रही हैं। मध्य प्रदेश के संबंध में यह रिपोर्ट किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपस्थिति-नामावली (मस्टर-रोल) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की सूची, भूमि-रैकॉर्ड तथा प्रदूषण-नियंत्रण बोर्ड जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता संबंधी अनुदेश लागू कर दिए गए हैं। केन्द्र सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को पारदर्शिता के बारे में तथा अवर्गीकृत सूचना तक पहुंच के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए हैं। इसने (केन्द्र सरकार ने) इस प्रयोजन से दिल्ली में, जनता से परस्पर विचारशीलता, क्रियाशीलता और प्रभावशीलता वाले चुनिन्दा विभागों से सूचना और सुविधा-काउंटर खोलने के लिए भी कहा हैं।

Indian Offer of Inspection of Chemical Weapons

36. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in the Times of India (New Delhi) dated the 27th June, 1997 under the caption "India throws open chemical weapons stocks for inspection"; if so, Government's reaction thereto;

(b) whether Government have taken enough safeguards to ensure that country's security is not compromised; and

(c) if so, the details thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) Yes, Sir. India is an original State Party to the Chemicals Weapons Convention which entered into force on 29th April, 1997. The convention requires States Parties to provide certain declarations within stipulated time schedules. India's declarations were made in keeping with the treaty obligations.

(b) and (c) India considers the CWC to be a model disarmament agreement and has asked the countries, that have not yet done so, to complete their ratification proceedings, in order to make the CWC genuinely universal and comprehensive. To date 95 countries, inclduing the USA and China have ratified this Treaty. Government remains fully committed to taking the necessary steps to safeguard India's security and national interest against all eventualities and Government's decision is in keeping with its commitments.

पड़ोसी देशों के संबंध मधुर बनाने हेतु वार्ता

*37. **प्रो0 राम बख्श सिंह वर्मा** : क्या प्रावधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान सरकार ने पड़ोसी देशों से अपने संबंध बनाने के लिए कोई वार्ता की हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) पड़ोसी देशों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री सलीम इकबाल शेरवानी**) : (क) से (ग) पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत का देश-वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार हैं:-

पाकिस्तान:

सरकार पाकिस्तान के साथ विश्वास, मित्रता और सहयोग के संबंध में स्थापित करने की इच्छुक हैं और द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया मसलों को शन्तिपूर्ण ढंग से हल करना चाहती हैं। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री देव गौड़ा ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को भेजे गए अपने बधाई पत्र में पारस्परिक हितचिंता के मुद्दों पर उपयुक्त स्तर पर दोनों देशों के बीच व्यापक बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था । इस पहल के परिणाम-स्वरूप नई दिल्ली में 28 से 31 मार्च, 1997 तक विदेश सचिव स्तर की बातचीत पुनः आरंभ हुई। माले में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने 12 मई, 1997 को द्विपक्षीय बातचीत के लिए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ

मुलाकात की थी। दोनों प्रधान मंत्रियों ने अपने-अपने विदेश सचिवों को ऐसे सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए बातचीत जारी रखने का निदेश दिया जिनके आधार पर द्विपक्षीय बातचीत आगे बढ़ाई जानी थी। विदेश सचिवों की 19-23 जून, 1997 तक इस्लामाबाद में बैठक हुई थी और बातचीत के परिणामस्वरूप एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ था जिसमें दोनों देशों के बीच चर्चा में आने वाले मुद्दों का उल्लेख किया गया था और उसके लिए कार्यकारी दल सहित तंत्र के गठन का प्रावधान था। वक्तव्य में दोनों देशों के बीच व्यापक, दूरगामी और स्थायी बातचीत के आधारों का प्रावधान हैं। हम विश्वास, मित्रता और सहयोग के संबंध में स्थापित करने के उद्देश्य से पाकिस्तान को एक विशाल मंच पर लाने के लिए अपने प्रयासों में इसे पहले कदम के रूप में देखते हैं।

नेपाल और भूटान :

भारत के प्रधान मंत्री ने 5 से 7 जून, 1997 तक नेपाल की सरकारी सदभावना यात्रा की। इससे पूर्व अगस्त, 1996 में नेपाल के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आए थे। तत्कालीन विदेश मंत्री (अब प्रधान मंत्री) ने विदेश सचिव के साथ 10 से 12 अगस्त, 1996 तक थिंपु की यात्रा की थी। महामहिम जिम्मे सिंगे वांग्चुक 4 से 7 मार्च, 1996 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए थे। 1997 में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद माले से लौटते समय भी महामहिम नई दिल्ली में रूके थे। इन सभी अवसरों पर हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और उत्कृष्ट संबंध प्रदर्शित करते हुए अत्यंत वातावरण में अनेक विषयों पर बातचीत हुई जिनमें द्विपक्षीय और आपसी हित के अन्य मामले शामिल हैं।

बंगलादेश :

माले में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान 11 मई, 1997 को हमारे प्रधान मंत्री और बंगलादेश की प्रधान मंत्री के बीच नदी-जल के बंटवारे, प्रस्तावित मोटर वाहन करार और आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ाने की आवश्यकता सहित कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती कमला सिन्हा ने 30 जून, 1997 को हांकांग में बंगलादेश के विदेश मंत्री श्री अब्दुसनद आजाद से मुलाकात की। जिन मसलों पर चर्चा हुई उनमें द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन और उपक्षेत्रीय सहयोग के मसले शामिल थे।

श्रीलंका:

श्रीलंका के प्रधान मंत्री की ओर से भारत के प्रधान मंत्री को बधाई का संदेश लेकर आए, 24-25 अप्रैल,1997 की अपनी भारत यात्रा के दौरान श्रीलंका के विदेश मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री के साथ बैठक के दौरान अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध और सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने के हमारी सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने श्रीलंका की आंतरिक स्थिति के बारे में भी बताया और उनके विस्थापित लोगों के पुर्नवास के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी चर्चा की। प्रधान मंत्री ने जाफना में पुनर्वास कार्यक्रम के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति के रूप में सहायता देने का आश्वासन दिया और दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने की प्रक्रिया में भारत की इच्छा के बारे में भी बताया। श्रीलंका में संजातीय समस्या कां शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए सुलझाए जाने के प्रति अपने समर्थन की बात को भी दोहराया।

मालदीव:

पर्यावरण और वन मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ ने मालदीव के तकनीकी शिक्षा संस्थान, जो विदेश मंत्रालय के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अनतर्गत बनाया गया हैं, के औपचारिक उदघाटन के लिए 3 से 5 मई, 1997 तक मालदीव की यात्रा की। भारत और मालदीव के बीच दूरस्थ शिक्षा से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप दिया जा रहा हैं।

चीन :

हाल के वर्षों में भारत-चीन सम्बन्धों में परिपक्वता तथा सार्थकता आई हैं। सीमा के प्रश्न सहित बकाया मसलों के समाधान की खोज जारी रखते हुए, हमने सभी क्षेत्रों में पारस्परिक लाभ के सहयोग को आगे बढ़ाने की कामना की हैं। हम एक रचनात्मक तथा सहयोगात्मक सम्बन्धों की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं।। भारत तथा चीन इस संम्बन्ध के प्रति और अधिक आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय वस्तुओं को प्रदान करने के

लिए सहमत हुए हें। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार के महत्वपूर्ण विस्तार पर काम करने के लिए संयुक्त आर्थिक समूह की आगामी बैठक आयोजित करने पर सहमति हो गई है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर भारत-चीन के उप-समूह दोनों पक्षों के बीच कार्यात्मक सहयोग में अभिवृद्धि करने के अवसर जुटाने का काम

करेंगे। दोनों देश सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को भी सुदृढ़ कर रहें हैं।

Bilateral Agreements with Nepal

*38. SHRI SOM PAL: SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has granted Nepal a trasit route to Bangladesh through Indian territory;

(b) if so, what are the details and the reasons therefor;

(c) whether there have been bilateral agreements on some other issues with Nepal;

(d) if so, the details thereof; and

(e) in what manner all these would benefit India?

THE PRIME MINISTER (SHRI I.K. GUJRAL): (a) to (e) The Prime Minister of India paid an official goodwill visit from 5—7 June, 1997 to Nepal. During the visit, Nepal's request for an additional transit route to Bangladesh *via* Phulbari was accepted. It was also agreed that the modalities and working arrangements will be decided within the next two months. The new arrangements would be reviewed six months thereafter.

The Trade Treaty, valid for five years, was revised and renewed through exchange of letters on December 3, 1996. India has agreed to provide access, free of customs duties, and quantitative restrictions, to all articles manufactured in Nepal, except three groups of items, namely alcohol, tobacco and cosmetics. A Memorandum of Understanding on Civil Aviation matters was signed during the Prime Minister's visit to Nepal.

The agreed changes in the Trade Treaty would increase bilateral trade, offer a chance for achieving a greater trade balance, as well as enable our neighbour, to provide a greater range of articles of Nepalese manufacture to India. The MOU on Civil Aviation should facilitate significant growth in business and tourism between the two countries.

findings of the Enquiry into the Amarnath Tragedy

*39. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that compensation for all the deceased in the last year's Amarnath tragedy has not been paid;

(b) if so, what is the status of compensation as on date, given both by the Jammu and Kashmir Government and the Central Government; and

(c) what were the findings of the investigation into the tragedy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) and (b) A total of 243 persons had died during the Amarnath Yatra tragedy in August 1996. An ex-gratia relief of Rs. 2 lakhs per deceased pilgrim is being disbursed to the next of kin by the concerned State Government authorities. The Government have released, till date, an amount of Rs. 372 lakhs to the various State Governments towards payment of ex-gratia relief to the families of 186 pilgrims whose bodies have been identified so far. This amount is being shared at 3:1 ratio between the Prime Ministrer's Relief Fund and Government of Jammu & Kashmir. In addition, Government of Jammu & Kashmir has released the ex-gratia relief for 5 security force personnel who had also died during the tragedy which has been disbursed through the concerned Force Headquarters. The State-wise details of